

सहकारिता से बने उत्पादों की ब्रांडिंग करें : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि जरूरतमंद व्यक्ति सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सके। इस संकल्प को गति देने में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका

- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की स्टेट अपेक्स कमेटी की प्रथम बैठक
- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत वर्षभर आयोजित होंगे जनजागरूकता कार्यक्रम
- ‘नया सहकारी कोड सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम कदम’



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने ‘अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025’ का मोमेन्टो भेंट किया। इस दौरान बैठक में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

निभाती है। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ राज्य सरकार प्रदेश के सभी गांवों को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने के लिए काम कर रही है। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित सहकारिता विभाग की स्टेट अपेक्स कमेटी की प्रथम बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता के माध्यम से देश के सभी वर्ग सशक्त हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहकारिता से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान, सहकार मेले, सदस्यता अभियान और

कार्यशालाओं सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता के साथ ही कृषि, राजस्व, पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पशुपालन जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े समस्त विभाग भी इन कार्यक्रमों में अपना सक्रिय योगदान दें। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सहकारिता अधिनियम को और प्रासंगिक बनाने के लिए नया सहकारी कोड तैयार किया जा रहा है। यह कोड सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण की दिशा में व्यापक सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटीकरण करते हुए प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जाए। पैक्स के कंप्यूटीकरण का कार्य भी नियत

समयावधि तक पूर्ण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में घोषित नवीन गोदामों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण और नियत समय अवधि में पूर्ण किया जाए, ताकि इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि गोदामों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं तथा फसलों की स्टोरेज के संबंध में कैलेण्डर भी जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग एवं राजीविका को आपसी समन्वय बनाते हुए काम करें, जिससे सहकारी बैंक की मजबूत होंगे तथा महिलाओं को आर्थिक संबल भी मिलेगा। उन्होंने सहकारी संस्थाओं द्वारा बने उत्पादों की ब्रांडिंग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे समितियों की आय में बढ़ोतरी हो सके। बैठक में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता मंजू राजपाल ने प्रस्तुतिकरण

के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत की जा रही विभागीय गतिविधियों की कार्य योजना की जानकारी दी। इस दौरान सहकारिता विभाग की गतिविधियों के संबंध में लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री को सहकारिता राज्य मंत्री ने ‘अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025’ का मोमेन्टो एवं विभागीय अधिकारियों ने सहकारिता से बने विभिन्न उत्पाद भी भेंट किए।

बैठक में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आरसीडीएफ एवं जिला संघों का लाभ 400 करोड़ के पार पहुंचा

जयपुर। राजस्थान राज्य में दुग्ध डेयरी सहकार से समृद्धि का सपना साकार होने लगा है। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और उससे सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभ के सभी पैमानों, टर्नओवर, सरस घी और दुग्ध उत्पादों की बिक्री, महिलाओं की दुग्ध क्षेत्र में सहभागिता, राजस्व ग्राम तक दुग्ध सहकारी समितियों की पहुंच आदि के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। फेडरेशन की सफलताओं के पीछे सरस अभूतम, दूध का दूध पानी का पानी और एक जिला एक उत्पाद जैसे अभियान और सरस घी के सभी पैक्स में क्यूआर कोड और राजस्थान में एक साथ सरस मिठाई का विपणन जैसे नवाचारों का अहम योगदान रहा है।

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रशासक और प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि

- दुग्ध डेयरी सहकार से समृद्धि. राजस्थान में दुग्ध क्रांति के नये कीर्तिमान
- सरस घी की बिक्री में तोड़े सारे रिकॉर्ड

वित्तीय वर्ष 2024-25 आरसीडीएफ एवं सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों ने रिकार्ड 400.85 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है जो फेडरेशन की स्थापना के 47 वर्षों में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह लाभ 298.61 करोड़ रुपये था। इस प्रकार आरसीडीएफ के कुल लाभ में 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि आरसीडीएफ के पशु आहार संयंत्रों में कच्चे माल के क्रय मूल्य में भारी कमी

और संयंत्रों की उत्पादन लागत में कमी के कारण पशु आहार संयंत्रों के लाभ में भी 77 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरसीडीएफ के पशु आहार संयंत्रों सहित सभी इकाइयों का लाभ 65.44 करोड़ रुपये था जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 116.07 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

भारद्वाज ने बताया कि आरसीडीएफ के 47 वर्षों के इतिहास में पहली बार आरसीडीएफ एवं इससे सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों का टर्नओवर 10 हजार करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरसीडीएफ एवं दुग्ध संघों का टर्नओवर 9505.14 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 8237.33 करोड़ रुपये था। इस प्रकार आरसीडीएफ के टर्नओवर में 15.40 प्रतिशत में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

उद्योगपति को निरुद्ध करने का आदेश रद्द

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के एक उद्योगपति को विदेशी मुद्रा के संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत एक साल के लिए निरुद्ध करने के आदेश को रद्द करते हुए उसे तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस आशुतोष कुमार ने यह आदेश पीयूष नवलखा की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हर्षवर्धन नंदवाना ने अदालत को बताया कि यूको बैंक, जोहरी बाजार ने कस्टम विभाग को शिकायत देकर विदेश में लेनदेन की जानकारी दी थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता का लुक आउट संकुलत जारी किया। वहीं 22 जुलाई, 2024 को दुबई जाते समय याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की गई।

शिकायत निराकरण समिति की बैठक

जयपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल कटाई प्रयोगों पर एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निस्तारण हेतु बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में शासन सचिव ने भीलवाड़ा जिले के रबी 2023-24 की फसल कटाई के 9 पटवार मंडलों के 33 फसल कटाई प्रयोगों की आपत्तियों के निस्तारण हेतु जिले के अधिकारियों एवं बीमा कम्पनी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर योजना प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही कर आपत्तियों का निस्तारण किया।

पूर्व मंत्री भाया और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार

- हाईकोर्ट ने दस दिन में जांच में शामिल होने के लिए आदेश

ऐसे में सभी एफआईआर की जांच एक आईपीएस से कराने की प्रार्थना भी नहीं मानी जा सकती।

याचिकाओं में कहा गया कि गत विधानसभा चुनाव हारने के बाद याचिकाकर्ता, उसके रिश्तेदार और दोस्तों सहित उससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी के प्रभाव से राजनीतिक द्वेषता के चलते डेढ़ दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज कराई गई। सत्ताधारी दल के सदस्यों और समर्थकों ने याचिकाकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। सभी एफआईआर में लगाए गए आरोप अस्पष्ट, बेतुके और व्यावहारिक

रूप में असंभव हैं। इन एफआईआर के अधिकांश शिकायतकर्ता सत्तारूढ़ दल के समर्थक हैं। ऐसे में उन्हें आशंका है कि इन मामलों की जांच निष्पक्ष नहीं होगी। ऐसे में लंबित एफआईआर को रद्द किया जाए। इसके अलावा इन एफआईआर और भविष्य में दर्ज होने वाली एफआईआर की संयुक्त रूप से निष्पक्ष जांच बारां व झालावाड़ जिले के अलावा अन्य जगह पदस्थापित आईपीएस अधिकारी से कराई जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता एक ओर तो इन एफआईआर को रद्द करने की गुहार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन्होंने एफआईआर की संयुक्त रूप से एक अधिकारी से जांच की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हर मामले के तथ्य, अपराध की प्रकृति और शिकायतकर्ता अलग-अलग हैं। इन

एफआईआर में अवैध खनन, नगर निगम के फर्जी दस्तावेज, फर्जी पट्टा और वित्तीय अनियमिता सहित अन्य अलग तरह के आरोप हैं। ऐसे में इनकी संयुक्त रूप से जांच नहीं हो सकती। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान जांच अधिकारियों पर दुर्भावना का भी कोई आरोप नहीं लगाया है। अदालत ने पूर्व में अंतरिम आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद याचिकाकर्ता जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा किसी आरोपी को यह अधिकार नहीं है कि मनचहै अधिकारी से मनचहै दिशा में जांच कराए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को दस दिन में जांच में शामिल होने को कहा है।

प्रबुद्धजन राजनीतिक पार्टियों का अध्ययन करके जुड़ता है भाजपा से : मदन राठौड़



भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने समाज के कई प्रबुद्धजनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई।

- ‘भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस, आम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ग्रहण की पार्टी की सदस्यता’

सी राजनीतिक पार्टी देश को समृद्ध कर सकती है, देश का मान बढ़ा सकती है और देशवासियों को सुरक्षा दे सकती है। भाजपा ही देश में ऐसी पार्टी है जो एक परिवार का नहीं, देश के 140 करोड़ भारतीय के विकास की चिंता करती है। इस चिंतन मनन के बाद आज समाज का अधिकांश प्रबुद्धजन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। भाजपा परिवार में आने वाले प्रबुद्धजन अकेले नहीं हैं, इनका समाज में एक प्रभुत्व है और इनका आभामंडल भी है, इनके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले भी भाजपा परिवार से जुड़ेंगे। इससे भाजपा और मजबूत होगी तथा भाजपा को बल मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कथन जो आज हमारा दुश्मन है वो कल हमारा समर्थक बने। इस पर भारतीय जनता पार्टी का

प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में विधायक बाल मुकुंदचारा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री पिकेश पोरवाल, भाजपा कार्यालय प्रभारी पिकेश पारीक, भाजपा नेता रवि नैय्यर, चन्द्रमोहन बटवाड़ा ने नए सदस्यों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस दौरान वार्ड 95 पार्षद प्रत्याशी मनोज ठाकुरानी, कांग्रेस महिला पूर्व महासचिव अंजना त्रिलोकानी, जवाहर नगर सेक्टर 2 अध्यक्ष रमेश हरपालानी, वार्ड उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मयंक त्यागी, लक्ष्मण टेकचंदानी, सेक्टर 4 अध्यक्ष गणेश राजपाल, मुरली पंजाबी सहित 34 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा इंडिया बुक आफ़ रिकॉर्ड्स में दर्ज

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेशभर में डीएलपी सड़कों की गुणवत्ता जांच एवं सड़क गुणवत्ता के प्रति जनजागरूकता हेतु आयोजित की जा रही सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा (सगुनि) को इंडिया बुक आफ़ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के सभागार में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स के पदाधिकारियों ने मुख्य अभियंता गुण नियंत्रण जसवंत खत्री को इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह प्रदान किया।

उपमुख्यमंत्री दिवा कुमारी के निर्देशन में मुख्य अभियंता गुणवत्ता नियंत्रण जसवंत खत्री के नेतृत्व में निकाली जा रही इस यात्रा ने किसी राज्य में डीएलपी सड़कों की गुणवत्ता जांच हेतु तय की गई सर्वाधिक दूरी के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। अब तक इस यात्रा के माध्यम से 11200 किमी की दूरी तय की जा चुकी है जबकि अभी 10 अन्य जिलों में पहुंचनी शेष है। मुख्य अभियंता जसवंत खत्री ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं निदेशावली तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत् 2082 को, सड़क गुणवत्ता निरीक्षण (सगुनि) यात्रा, श्री गंगानगर जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से शुरू की गई थी जो कि दौसा होती हुई गुरुवार को जयपुर शहर में पहुंची है एवं 33 जिला मुख्यालयों से गुजरती हुई बुद्ध



राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के सभागार में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स के पदाधिकारियों ने मुख्य अभियंता गुण नियंत्रण जसवंत खत्री को इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह प्रदान किया।

पूर्णिमा के दिन श्री गंगानगर में पूर्ण होगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की गुण नियंत्रण ईकाई के नेतृत्व में निकाली जा रही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के दोष निवारण अवधि में संवेदकों द्वारा किये जाने वाले रख रखाव का मूल्यांकन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों से करवाया जाना है। इसके तहत पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को लॉटरी के माध्यम से संबंधित जिले के विभिन्न खण्डों की

सड़कों की जांच हेतु भेजा जाता है। जांच रिपोर्ट में खराब पाई गई सड़कों के संबंध में कार्यवाही हेतु मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव के माध्यम से संबंधित संवेदक एवं अभियंता को कार्यवाही हेतु पत्र भेजकर सड़क की गुणवत्ता को ठीक करवाया जाता है। यात्रा के दौरान अब तक 24 जिलों में 11202.89 किमी दूरी की 2224 सड़कों की गुणवत्ता की जांच की जा चुकी है। श्री गंगानगर में लगभग 325 किमी की 38 सड़कों, बीकानेर में 378 किमी की 53 सड़कों, जैसलमेर में

424 किमी की 42 सड़कों, बाड़मेर में 564 किमी की 69 सड़कों, जालौर में 396 किमी की 36 सड़कों, सिराही में 177 किमी की 33 सड़कों, राजसमंद में 333 किमी की 50 सड़कों, उदयपुर में 630 किमी की 97 सड़कों, डूंगरपुर में 493 किमी की 47 सड़कों, बांसवाड़ा में 244 किमी की 49 सड़कों, प्रतापगढ़ में 434 किमी की 49 सड़कों, चित्तौड़गढ़ में 226 किमी की 43 सड़कों, भीलवाड़ा में 311 किमी की 51 सड़कों, टोंक में 373 किमी की 50 सड़कों, बूंदी में 256

- अब तक 11200 किमी लम्बाई की सड़कों की जांच कर बनाया रिकॉर्ड

किमी की 37 सड़कों, कोटा में 670 किमी की 252 सड़कों, झालावाड़ में 707 किमी की 177 सड़कों, बारां में 632 किमी की 139 सड़कों, सवाईमाधोपुर में 774 किमी की 144 सड़कों, करौली में 660 किमी की 120 सड़कों, भीलपुर में 383 किमी की 84 सड़कों, भरतपुर में 610 किमी की 182 सड़कों, अलवर में 700 किमी की 242 सड़कों तथा दौसा में 500 किमी की 140 सड़कों की जांच यात्रा के दौरान करवाई जा चुकी है।

इस दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। इस दौरान अतिथियों ने जयपुर जिले के विभिन्न खण्डों के निरीक्षण हेतु पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों के वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव टी सी गुप्ता, समस्त मुख्य अभियंता एवं अन्य अधिकारी तथा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

सीसीटीवी कैमरों का शिलान्यास

जयपुर। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने वार्ड 149 पंचवटी सर्किल राजा पार्क में विधायक कोष द्वारा प्रदत्त राशि 16 लाख रुपये की लागत से लगने वाले 21 सीसीटीवी कैमरों का शिलान्यास किया। नटवर कुमावत ने बताया कि पंचवटी सर्किल के पास कुछ महीने पहले चोरों के द्वारा एक मोबाइल की दुकान के ताले तोड़कर 2 करोड़ रुपये के मोबाइल चोरी हुए थे, उस समय क्षेत्रीय विधायक सराफ घटनास्थल पर गए थे, और व्यापारियों को आश्वासन दिया था, की जल्दी यहां पंचवटी सर्किल के निरीक्षण हेतु पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों के वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

‘जैसलमेर में कर्रा रोग के प्रभावित गांवों में बीमार पशुओं के सैंपल लिए गए’

जयपुर। जैसलमेर जिले में कर्रा रोग की वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए पशु चिकित्सकों के तीन सदस्यीय दल ने प्रभावित जिले के करीब दो दर्जन गांवों में पहुंचकर दर्जनों बीमार पशुओं के सैंपल लिए हैं। दल की प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया गया कि कर्रा रोग प्रारंभिक लक्षण वाले पशुओं की संख्या काफी कम हो गई है। पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया है कि जयपुर स्थित पीजीआईवीआईआर के वीसीसी ईंचार्ज अस्तिटेट प्रोफेसर डॉ. सुरेश कुमार के निर्देशन में पीजीआईवीआईआर के अस्तिटेट प्रोफेसर डॉ. विकास पटेल व डॉ. संदीप कुमार शर्मा को जांच लिए भेजा गया। इस टीम ने जैसलमेर जिला मुख्यालय के आसपास के गांवों व पोकरण तहसील के दो दर्जन से अधिक गांवों में सैंपल लिए हैं। इस टीम ने दो दिन तक जिले के गांव बड़ोड़ा, रिदवा, बंबारों की ढाणी, गांव आसायच, डाबला, दंबारी, सोरों की ढाणी सहित करीब दो दर्जन गांवों में बीमार पशुओं के सैंपल लेकर जिला कलेक्टर व पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. उमेश कुमार को अवगत करवाया है। जोराराम कुमावत ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों से बीमार पशुओं के लिए गए सैंपल का लैब में गहन परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद वस्तुस्थिति और साफ हो सकेगी।

कुमावत ने बताया कि चिकित्सकों के दल ने जिन क्षेत्रों में पशुओं के सैंपल लिए हैं, वहां कर्रा रोग के प्रारंभिक लक्षण तो नहीं मिले हैं लेकिन कुछ अन्य बीमारियों के लक्षण जरूर मिले हैं जिनके लिए उनका उपचार चल रहा है। खासकर पशुओं में पोणन व फास्फोरस की कमी, बैक्टीरियल रोग की आशंका है।